

Shodhparak Vaicharik Patrika

RNI No.: UPBIL/2013/55327

ed Journal

ISSUE-7 (Part-2) March- 2019

Indexed with
Google

Impact Factor
= 5.921 (2018)
= 0.543 (2015)
= 6.038 (2018)

Shrikhala
UGC
Approved listed

The Research Series

द्विभाषीय - मासिक

Shrinkhala

श्रिखला

A Multi-Disciplinary International Journal



Shrinkhla Ek Shodhparak Valcharik Patrika

Contents (Hindi Papers)

VOL-8* ISSUE-7* (Part-2) March-2019

S.No.	Particulars	Subject	Page No.	
			From	To
1	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का समीक्षात्मक अध्ययन सर्पराज रामानन्द सागर, भागलपुर, बिहार, भारत	अर्थशास्त्र	H-01	H-05
2	बीएड कॉलेज में कार्यरत शिक्षक - शिक्षकाओं की अपने कार्य सन्तुष्टि का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रमोद कुमार शर्मा, जयपुर, राजस्थान, भारत	शिक्षा शास्त्र	H-06	H-08
3	दूरवर्ती शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कृष्णा, जयपुर, राजस्थान, भारत	शिक्षा शास्त्र	H-09	H-10
4	छत्तीसगढ़ के शासकीय व अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों के दृष्टिकोण से संपूर्ण गुणवत्ता मूल्यांकन : प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं अवधि के संदर्भ में एक अध्ययन सत्यप्रकाश यादव एवम् प्रकृति जेम्स, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, भारत	शिक्षा शास्त्र	H-11	H-15
5	भारत में मुस्लिम महिलाएं एवं महिला सशक्तिकरण- तीन तलाक एक्ट के विशेष संदर्भ में संक्षिप्त अध्ययन ज्योति मेहरा, अलवर, राजस्थान, भारत	राजनीतिक विज्ञान	H-16	H-20
6	वैदिक समाज में स्त्री और उनकी दशा दिनेश सिंह, गंगेश्वरी, अमरोहा, भारत	इतिहास विभाग	H-21	H-24
7	राजस्थानी भाषा के विकास में चारण साहित्य का योगदान एकता, जोधपुर, राजस्थान, भारत	इतिहास विभाग	H-25	H-27
8	राजस्थान के भरतपुर जिले में आर्थिक विकास एवं अपराधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन शैलेन्द्र कुमार सैदावत, जयपुर, राजस्थान, भारत	भूगोल	H-28	H-31
9	विकास खण्ड दूबेपुर (जनपद सुलतानपुर, उ०प्र०) का सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण रवि कुमार, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत	भूगोल	H-32	H-37
10	पत्रकारिता में प्रगतिवादी दृष्टिकोण के हिमायती- हेतु भारद्वाज - एक परिचय अशोक धवन, अजमेर, राजस्थान, भारत	हिन्दी	H-38	H-40
11	महिला सशक्तिकरण व भारतीय कानून निधि शर्मा, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत	विधि विभाग	H-41	H-44
12	मोटोपे से ग्रसित कार्यशील एवं गृहिणी महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर पर योगासन, व्यायाम एवं आहारिय परामर्श के सम्मिलित प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन प्रगति देसाई एवम् मेघा परमार, इन्दौर (म.प्र.) भारत	गृहविज्ञान	H-45	H-49
13	महात्मा ज्योतिबा फुले के सामाजिक विचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन पीयूष हर्षवाल, बूरा, राजस्थान, भारत	राजनीतिक विज्ञान	H-50	H-53
14	भारत में गठबंधन सरकारों का विदेश नीति पर प्रभाव हंसा चौधरी, जयपुर, राजस्थान, भारत	राजनीतिक विज्ञान	H-54	H-57
15	गुटनिरपेक्षता : उद्देश्य, विशेषताएं एवं प्रासंगिकता अग्निदेव, अलवर, राजस्थान, भारत	राजनीतिक विज्ञान	H-58	H-65

छत्तीसगढ़ के शासकीय व अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों के दृष्टिकोण से संपूर्ण गुणवत्ता मूल्यांकन : प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं अवधि के संदर्भ में एक अध्ययन



सत्यप्रकाश यादव
शोधार्थी,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त)
विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़, बिलासपुर, भारत

प्रकृति जेम्स
सहायक प्राध्यापक
शिक्षा शास्त्र विभाग,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त)
विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़, बिलासपुर, भारत

सारांश

वर्तमान समय में शिक्षक से हमारी अपेक्षाएँ बढ़ गयी हैं, आज हम जहाँ स्वयं विद्यार्थी, समाज, शाला, व्यवसाय इत्यादि के प्रति समर्पित होना है, वहीं विषय-विशेषज्ञ, चिंतक के रूप में भी अपने को साबित करना है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1998 के अनुसार शिक्षा के चार स्तम्भ- ज्ञान के लिए सीखना, स्व-अस्तित्व के लिए सीखना, कार्य के लिए सीखना एवं सहअस्तित्व के लिए सीखना हैं, इन चार स्तम्भों का आधार शिक्षक है। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, इन अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु एक कुशल शिक्षक तैयार करना होगा और यह तभी संभव है जब देश में शिक्षक को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए मानक के अनुसार सुविधा सम्पन्न उच्च कोटि शासकीय-अशासकीय की शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाएँ हों।

मुख्य शब्द : NCERT, NUEPA, डाईट, गुणवत्ता।
प्रस्तावना

शिक्षा की दृष्टि से "प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण", "गुणवत्तापूर्ण सभी के लिए शिक्षा", आदि राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख लक्ष्य रहें हैं। इसी क्रम में 8 से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देना, आज उनका मौलिक अधिकार बन गया है, साथ ही यह लक्ष्य देश का संवैधानिक उत्तरदायित्व भी हो गया है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में हम यह कह सकते हैं शिक्षण जैसे उत्तम कार्य में शिक्षक की भूमिका केन्द्रीय हो गई है। वर्तमान समय में शिक्षक से हमारी अपेक्षाएँ बढ़ गयी हैं, आज उसे जहाँ स्वयंविद्यार्थी, समाज, शाला, व्यवसाय इत्यादि के प्रति समर्पित होना है, वहीं विषय-विशेषज्ञ, चिंतक के रूप में भी अपने को साबित करना है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1998 के अनुसार शिक्षा के चार स्तम्भ- ज्ञान के लिए सीखना, स्व-अस्तित्व के लिए सीखना, कार्य के लिए सीखना एवं सहअस्तित्व के लिए सीखना हैं, इन चार स्तम्भों का आधार शिक्षक है। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, इन अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु एक कुशल शिक्षक तैयार करना होगा और यह तभी संभव है जब देश में शिक्षक को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए मानक के अनुसार सुविधा सम्पन्न उच्च कोटि शासकीय-अशासकीय की शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाएँ हों। देश के सभी राज्यों में ऐसी संस्थाओं के गठन हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये जा रहे हैं।

इसी तारतम्य में स्थानीय एवं जिला स्तर पर प्रारंभिक शालाओं के शिक्षकों को सेवापूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण देने तथा सभी प्रकार के उत्तरदायित्व और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाएँ संचालित की गयी हैं और इनकी संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। इन संस्थाओं के प्रमुख लक्ष्य निम्नानुसार वर्णित हैं -

1. प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण करना।
2. प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफल बनाने की दृष्टि से अकादमिक तथा अन्य संसाधनों की पूर्ति करना।
3. प्रशिक्षण संस्थाएँ स्वयं को इतना उन्नत बनावेगी कि उनसे प्रारंभिक शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहायता मिल सके।
4. जिले की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिये योजनाओं का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन करना।

अध्यापकों को उच्चस्तरीय सेवापूर्व-सेवाकालीन प्रशिक्षण देना। अध्यापक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में आस-पास के संस्थानों का अधिकतम प्रयोग कर सकें। प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययन-अध्यापन की सहायक सामग्री का निर्माण करना तथा मूल्यांकन उपकरण निर्मित करना। शिक्षण अनुसंधान पर बल देना। शिक्षण एवं वंचित वर्ग के बच्चों की समावेशी शिक्षा दिश्यों को व्यवस्था करना।

उपरोक्त लक्ष्यों को पूरा करने हेतु प्रारम्भिक स्तर के शिक्षकों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण देने एवं प्रसार के संसाधन हेतु डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाएँ की गयीं। डी.एल.एड., अध्यापक शिक्षा का प्रारम्भिक पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य कक्षा आठवीं तक अध्यापकों को तैयार करना है। डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हमारे समाज की सहभागिता से सामाजिक विषमताओं को दूर करते हुए समावेशी स्कूल पर्यावरण में सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी आवश्यकता को पूर्ण करता है। शासकीय एवं अशासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को कार्य करते लम्बा समय बीत गया है अब लम्बे कार्य प्रणाली, अध्यापकीय व्यवहार, एवं दक्षता का मूल्यांकन का उपयुक्त समय आ चुका है। देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में शासकीय एवं अशासकीय शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं यह शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन संस्थानों को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) तथा सर्वशिक्षा अभियान जैसे महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का आधार मानते हुये, इन सभी प्रकार की अधुनातन सुविधायें एवं तकनीक को लक्ष्य कराने हैं जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा निदेश, नयी दिल्ली (NCTE) ने मानक व दिशा निर्देश निर्धारित किये हैं।

आधुनिकतावलोकन

बनर्जी (1967) ने भारत में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण पर अध्ययन किया। इनके अध्ययन के निम्न परिणाम थे कि शिक्षक प्रशिक्षण में बहुत सी कमियाँ थीं। परिवर्तनों और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिक्षक प्रशिक्षण में आमूल परिवर्तन और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिक्षक प्रशिक्षण में आमूल परिवर्तन आवश्यक था। मूल्यांकन व शिक्षण पद्धतियाँ पुरानी थीं।

मूलैया (1968) ने मध्यप्रदेश में शिक्षक प्रशिक्षण की स्थिति का अध्ययन किया। इस अध्ययन का निष्कर्ष यह प्राप्त हुआ कि मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय अभावग्रस्त थे। विद्यालयों में संसाधनों की कमी थी। मूल्यांकन और शिक्षण विधि परंपरागत थी। पुरुषों की संख्या महिलाओं की अपेक्षा अधिक थी।

गुप्ता (1982) द्वारा माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता पर अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के यह परिणाम निकले कि शिक्षक प्रशिक्षकों की शैक्षिक योग्यता एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण में सह संबंध होता है। शिक्षण अनुभवों का

प्रशिक्षण कार्य पर प्रभाव पड़ता है। समाजोपयोगी कार्य ध्यायसायीकरण सामुदायिक कार्य व शिक्षण पद्धति आदि का ज्ञान देना आवश्यक है।

गुप्ता (1982) द्वारा भारत में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया है। इस अध्ययन के ये परिणाम प्राप्त हुए कि 61 से 70 के बीच संस्थानों की वृद्धि हुई है। 63 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षण पुरुष थे। प्रशिक्षक संस्थानों की कार्य प्रणाली गांवों से संबंधित थे। केवल 18 प्रतिशत छात्र एम.एड. उपाधि प्राप्त थे। शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को महत्व नहीं दिया जाता था। स्थानीय संस्थानों की व्यवस्था से ठीक थी। वाद-वियाद विधि ज्यादा प्रयुक्त थी।

राय (1982) ने उत्तर प्रदेश तथा गुजरात के शिक्षा महाविद्यालयों और अभ्यास शिक्षण शालाओं (Practice Teaching Schools) से संबंधित समस्याओं पर अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला है कि :-

1. शिक्षा महाविद्यालयों एवं अभ्यास शालाओं के परिप्रेक्ष्य में अनेकों कमियाँ उजागर हुई हैं। शिक्षा महाविद्यालयों एवं अभ्यास शालाओं के बीच परस्पर सहयोग के अभाव के साथ-साथ यह भी पता चलता है कि शिक्षा महाविद्यालय के प्रशिक्षार्थियों द्वारा अभ्यास शालाओं में जाने से उनके कार्यक्रम, एवं अन्य नियमित गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होती है।
2. इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि अभ्यास शालाओं एवं शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रभावशाली सहयोग होना चाहिए।

सिन्हा (1982) ने बिहार में शिक्षक-शिक्षा विषय पर अध्ययन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि -

1. प्राथमिक स्तर पर लगभग 60 प्रतिशत शिक्षक-प्रशिक्षक बी.एड. प्रशिक्षित हैं परन्तु उनका कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया।
2. 70 प्रतिशत महाविद्यालय में स्वयं का भवन नहीं पाया गया और 65 प्रतिशत महाविद्यालयों में दयनीय स्थिति वाले भवन पाये गये।
3. अधिकांश शिक्षा महाविद्यालयों में स्टॉफ, पुस्तकालय, उपकरण तथा प्रयोगशाला अपर्याप्त पाये गये।
4. आधुनिक नवाचारी कार्यक्रमों का समावेश अभी तक शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों में नहीं हो पाया है।
5. सेवाकालीन प्रशिक्षण न तो प्रभावशाली ढंग से दिये जाते हैं और न ही अध्यापन अभ्यास कार्य कराने में पर्यवेक्षक शिक्षक पर्याप्त ध्यान देते।

अध्ययन का औचित्य

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA) तथा डाईट जैसी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं के द्वारा योजना के क्रियान्वयन, लक्ष्य प्राप्ति तथा उससे अपेक्षाओं पर किये गए राष्ट्र स्तरीय मूल्यांकन निष्कर्ष बहुत अधिक सकारात्मक एवं उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं।

इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ में संचालित डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में मानकों के अनुरूप कार्यों का मूल्यांकन करना विशेष शैक्षिक महत्व का होगा क्योंकि

शोध अध्ययन के निष्कर्ष के प्रकाश में जी.एल.एड. संस्थाओं की वास्तविक स्थितियों का ज्ञान प्राप्त होगा और समय रहते ही योजनाबद्ध ढंग से उनकी समस्याओं को सुधारने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इस शोध में यह पता लगाना कि छत्तीसगढ़ राज्य की शासकीय एवं अशासकीय जी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में सेवारत आचार्य अपने-अपने संस्थाओं कि प्रयासों, प्रयासों, किरायाकलापों, गुणवत्ता आदि सुविधाओं पर ध्यान दिया है उनकी सजगता इस ओर कितनी है। शिक्षण महत्व का है क्योंकि आचार्यों की ऐसी ही विशेषताओं, अवबोध तथा सजगता पर राज्य में जी.एल.एड. प्रशिक्षण की योजना की सफलता निर्भर करती है। तब प्रशिक्षण की योजना के लिए एक ऐसा शोध अध्ययन जिससे निम्नलिखित प्रश्नों के हल बूँदा जाये, छत्तीसगढ़ राज्य में सुदृढ़ शिक्षण व्यवस्था के लिए अत्यंत औचित्यपूर्ण होगा कि इस नवोदित राज्य में इस प्रकार का अध्ययन अभी आवश्यक नहीं हुआ है। इस सर्वेक्षणालेख अध्ययन के निष्कर्ष राज्य के लिए दिशा निर्देशक होगा।

अध्ययन का उद्देश्य
 प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं -
 शासकीय एवं अशासकीय जी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं प्रशिक्षण की क्षमता का अध्ययन करना।
 अध्ययन की परिकल्पना

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों की जांच हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाएँ बनायी गयी हैं -

1. शासकीय एवं अशासकीय जी.एल.एड. प्रशिक्षण की संस्थाओं में NCTE के मानक के अनुरूप प्रशिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने का सकारात्मक प्रयास किया जाता है।
2. शासकीय एवं अशासकीय जी.एल.एड. प्रशिक्षण की संस्थाओं में NCTE के मानक के अनुरूप प्रशिक्षण की निश्चित अवधि में ही प्रशिक्षण को पूरा करने का सकारात्मक प्रयास किया जाता है।

प्रस्तुत शोध विधि (Research Method)
 प्रस्तुत अध्ययन एक वर्णात्मक अध्ययन है जिसमें वर्णन विधि का उपयोग किया जायेगा।
नमूना (Sample)

नमूने के रूप में शासकीय एवं अशासकीय जी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत प्राचार्य हैं। छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में से 16 जिलों में शासकीय जी.एल.एड. एवं दो जिलों में दो बी.टी.आई संचालित हो रहे हैं। इन जिलों के 18 अशासकीय जी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं को यादृच्छिक विधि से चुना गया है।
अध्ययन के घर

प्रस्तुत अध्ययन में घर एवं उनके स्तर निम्नानुसार हैं -
स्वतंत्र चर (Independent Variable)

डाईट/जी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली द्वारा निर्धारित कार्यक्रम एवं मानक प्रस्तुत अध्ययन में स्वतंत्र चर हैं।

आश्रित चर (Dependant Variable)

शासकीय एवं अशासकीय जी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में सारपूर्ण गुणवत्ता का मूल्यांकन गुणात्मक सूचक (Indicator) द्वारा अध्ययन के आश्रित चर है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा वर्णित है, ये माध्यम से किया गया है।
उपकरण (Tool)

प्रस्तुत शोध अध्ययन में स्वनिर्मित उपकरण का उपयोग किया गया है।
 संस्था के प्राचार्य हेतु साक्षात्कार पत्रक प्रश्नों का विश्लेषण

1. जी.एल.एड. प्रशिक्षण की अवधि यो. वर्ष रखी गई है, क्या आप इसे उचित मानते हैं ?

हां	नहीं
94.45%	05.55%

94.45 प्रतिशत प्राचार्यों ने प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष उचित माना है जबकि 05.55 प्रतिशत प्राचार्यों ने इसे अस्वीकार किया है।

2. जी.एल.एड. प्रशिक्षण का शुल्क आपकी दृष्टि से उचित है।

हां	नहीं
77.78%	22.22%

77.78 प्रतिशत प्राचार्यों ने जी.एल.एड. का प्रशिक्षण शुल्क को उचित माना है जबकि 22.22 प्रतिशत प्राचार्यों ने इसे अस्वीकार किया है।

3. द्विवर्षीय प्रशिक्षण-अवधि के प्रत्येक वर्ष में कुल कार्य दिवस कम से कम 200 दिन का है। क्या इसे आप सुविधाजनक मानते हैं ?

हां	नहीं
94.45%	5.55%

94.45% प्राचार्यों ने प्रशिक्षण अवधि में 200 कार्य दिवस पर को उचित मानते हैं जबकि 5.55% प्राचार्य इस सुविधाजनक नहीं मानते हैं।

4. क्या प्रशिक्षण में प्रति सप्ताह 36 घण्टे कार्य करने का लक्ष्य पूरा होता है ?

हां	नहीं
88.89% (16)	11.11% (2)

88.89% प्राचार्यों ने स्वीकार किया है कि प्रशिक्षण में प्रति सप्ताह 36 घण्टे कार्य का लक्ष्य पूरा किया जाता है जबकि 11.11% प्राचार्य इसे नहीं मानते हैं।

5. क्या छात्राध्यापकों की उपस्थिति प्रायोगिक सहित अकादमिक कार्यों में 80 प्रतिशत तथा स्कूल इन्टरनशिप में 90 प्रतिशत हो पाती है ?

हां	नहीं
77.78% (14)	22.22% (4)

77.78% प्राचार्यों छात्राध्यापकों की उपस्थिति स्वीकारते हैं जबकि 22.22% प्राचार्य छात्राध्यापकों की उपस्थिति से संतुष्ट नहीं हैं।

6. जी.एल.एड. प्रशिक्षण के नये पाठ्यक्रम को कियान्वयन करके इसके माध्यम से छात्राध्यापकों को पहली कक्षा से आठवीं कक्षा के अध्यापन हेतु क्षमतावान व

प्राचार्य विचारों के अध्यापक तैयार करना है क्या आपके मत से इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नया पाठ्यक्रम सक्षम है ?

हां	नहीं
88.88% (16)	11.12% (4)

डी.एल.एड. के नये पाठ्यक्रम को 88.88% प्राचार्य सक्षम मानते हैं जबकि 11.12% प्राचार्य इसे सक्षम नहीं मानते।

7. क्या आपके मत से प्रशिक्षार्थियों की कक्षा समावेशी बनाने में समुदाय का सक्रिय सहयोग मिलता है ?

हां	नहीं
61.11% (11)	38.89 % (7)

61.11% प्राचार्यों ने समुदाय के सक्रिय सहयोग को माना है। 38.89% प्राचार्य समुदाय के सहयोग नहीं मिलने की बात करते हैं।

विवेचना

प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं अवधि पर प्राचार्यों के निष्कर्ष से यह कहा जा सकता है कि डी.एल.एड. पाठ्यक्रम की अवधि जो छह महीने में मानक अनुरूप दो सैद्धांतिक अवधि का होगा, उचित है इसे सभी प्राचार्यों ने भी स्वीकार किया है क्योंकि दो वर्ष की अवधि में विद्यार्थियों की सैद्धांतिक कक्षाएं, प्रयोगात्मक कार्य, इन्टर्नशिप जैसे कार्यक्रम को पूरा करना होता है, अतः यह अवधि उचित है। डी.एल.एड. का शुल्क NCTE के अनुरूप राज्य सरकार/संबंधित संबद्ध निकाय द्वारा समय समय निर्धारित की जाती है अतः ज्यादातर प्राचार्यों ने पाठ्यक्रम के शुल्क को भी स्वीकार किया है अधिकतर प्राचार्यों ने भी यह भी स्वीकार किया है कि प्रवेश व परीक्षा की अवधि को छोड़कर भी वर्ष में 200 दिन एवं प्रति सप्ताह 36 घण्टे की अवधि को पूरा कर पाठ्यक्रम को पूर्ण किया जाता है। प्राचार्यों ने इन्टर्नशिप में छात्राध्यापकों की उपस्थिति को गंभीरता से लिया है और छात्राध्यापकों द्वारा 90% उपस्थिति पूर्ण की जाती है NCTE मानक में प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य समाज की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक और लिंग अंतरों को दूर करते हुए समावेशी स्कूल पर्यावरण में सभी बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने की दुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना है प्राचार्यों ने संस्था की गुणवत्ता व पाठ्यक्रम की गुणवत्ता बनाये रखने में संस्था, समुदाय, पालक इत्यादि के सहयोग को स्वीकार है।

डॉ. चक्रवर्ती के अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के प्रारंभ में प्रशिक्षार्थियों की अभिवृद्धि, प्रशिक्षण पूरा करने पर प्राप्त अभिवृद्धि में परिवर्तन आना प्रशिक्षण के प्रति अत्यंत सकारात्मक अभिवृद्धि के विकास का संकेत देता है और सुविधा संपन्न प्रशिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता को निरूपित करता है। अतः डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं के उद्देश्य व अवधि का पालन करना प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता का सूचक है।

निष्कर्ष

- 94.45 प्रतिशत प्राचार्यों ने प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष उचित माना है जबकि 05.55 प्रतिशत प्राचार्यों ने इसे अस्वीकार किया है।
- 77.78 प्रतिशत प्राचार्यों ने डी.एल.एड. का प्रशिक्षण शुल्क को उचित माना है जबकि 22.22 प्रतिशत प्राचार्यों ने इसे अस्वीकार किया है।
- 94.45 प्रतिशत प्राचार्यों ने प्रशिक्षण अवधि में 200 कार्य दिवस पर को उचित मानते हैं जबकि 5.55 प्रतिशत प्राचार्य इस सुविधाजनक नहीं मानते हैं।
- 88.89 प्रतिशत प्राचार्यों ने स्वीकार किया है कि प्रशिक्षण में प्रति सप्ताह 36 घण्टे कार्य का लक्ष्य पूरा किया जाता है जबकि 11.11 प्रतिशत प्राचार्य इसे नहीं मानते हैं।
- 77.78 प्रतिशत प्राचार्यों छात्राध्यापकों की उपस्थिति स्वीकारते हैं जबकि 22.22 प्रतिशत प्राचार्य छात्राध्यापकों की उपस्थिति से संतुष्ट नहीं हैं।
- डी.एल.एड. के नये पाठ्यक्रम को 88.88 प्रतिशत प्राचार्य सक्षम मानते हैं जबकि 11.12 प्रतिशत प्राचार्य इसे सक्षम नहीं मानते हैं।
- 61.11 प्रतिशत प्राचार्यों ने समुदाय के सक्रिय सहयोग को माना है। 38.89 प्रतिशत प्राचार्य समुदाय के सहयोग नहीं मिलने की बात करते हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

चन्द्रशेखर, के. (2000)– एन इवैल्यूएटिव स्टडी आफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम इन आन्ध्रप्रदेश, पी-एच.डी. थिसिस, एजुकेशन श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरुपति।

चन्द्रशेखर, के. (2007)– “टीचर एजुकेशनर्स पर्सपेक्टिव्स आफ डाईट्स फेसीलिटीज एण्ड दीयर रिलेसनस टू सर्वेंट पर्सनल एण्ड डिमोग्राफिक वैरियेबल्स” पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन हरिनगर रिसर्च बडौदा, वाल्थूम 23 (2), अप्रैल 2017 पृष्ठ : 92-104।

डेलर्स, जे. एट. आल (1996)– “क्वालिटी टीचर्स तारिफ: दी टेजर विदिन रिपोर्ट टु यूनेस्को ऑफ दी इण्टरनेशनल कमीशन आन एजुकेशन फार दी ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी, पृष्ठ-146 पेरिस, यूनेस्को कोटेड इन दी इण्डियन जर्नल फार टीचर एजुकेशन, एन.सी.टी.ई., नई दिल्ली, वाल्थूम (1), अगस्त 1998।

वास, आर.सी.एण्ड जंगीरा, एन.के. (2004)– ए ट्रेण्ड रिपोर्ट, टीचर एजुकेशन थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, नई दिल्ली, एन.सी.ई.आर.टी पृष्ठ 782-789।

वीपा कृष्णा एण्ड सरोज आनन्द (2006)– गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिका अन्वेषिका 3 (2) दिसंबर 2006, पृष्ठ 75 से 80।

गवर्नमेंट आफ इंडिया (1989)– गाइडेंस आफ डाइट नई दिल्ली, मिनीस्ट्री आफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट आफ एजुकेशन कोटेड

- इन परामिटर्स इन एजुकेशन, वाल्यूम 23 (2), अप्रैल 2007।
- श्री ए. (1996)- एन इनवेस्टीगेशन इन्टू द परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट टीचर्स आन देयर टीचर ट्रेनिंग, अनपब्लिश एम.एड डिजिटेशन, एस.सी. शिक्षा विद्यालय, तिरुपति।
- श्री यशवती (2013)- "जयपुर जिले के बी. एस. टी. संस्थाओं में शैक्षिक गुणवत्ता हेतु किए जा रहे प्रयास"- एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, पी-एच.डी. थिसिस एजू. वनस्थली, राजस्थान।
- श्री विनीता (2009-10)- " छत्तीसगढ़ राज्य की जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं की सुविधाओं के विषय में प्रारंभिक शिक्षक-प्रशिक्षकों का प्रत्यक्ष बोध उनकी आयु, लिंग, शैक्षिक योग्यता तथा अध्यापन अनुभव के विशेष सन्दर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन रिसर्च थीसिस, बिलासपुर (छ.ग.)।

Multi-disciplinary Journal

Certificate of Paper Publication

Shrinkhala

E-ISSN
2349-980X
P-ISSN
2321-290X

SJIF- 5.921
GIF-0.543
IIJIF-6.038

RNI
UPBIL/2013/55327
Indexed
Google

Shrinkhala Ek Sodhparak Vaicharik Patrika

This is to certify that the paper titled, छत्तीसगढ़ के शासकीय व अशासकीय डी.एन.एड.
प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों के दृष्टिकोण से संपूर्ण गुणवत्ता मूल्यांकन : प्रशिक्षण के उद्देश्य
एवं अवधि के संदर्भ में एक अध्ययन

Authors	Designation	Department	College
ब्रजप्रकाश यादव	शोधार्थी	शिक्षा शास्त्र	पं. सुन्दरतात शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, भारत
प्रकृति जेम्स	महायक प्राध्यापक	शिक्षा शास्त्र	पं. सुन्दरतात शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, भारत

has been published in our UGC Approved International Journal

vol. 6 issue 7 month March (Part-2) year 2019

The mentioned paper is measured upto the required.

Ajaya
Dr. Rajeev Misra 4
(Editor/Secretary)

Dr. Asha Tripathi
Dr. Asha Tripathi
(Vice-President)

Social Research Foundation

Non Governmental Organisation

128/170, H-Block, Kidwai Nagar, Kanpur - 208011

10/05/2022/ The Ram

28) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
Mrs. Meshram, Khursipar Bhilai

29) 'वर्तमान में कृषि श्रमिकों की समस्याएँ : कुमाऊँ के विशेष संदर्भ में
डॉ. निशा, डॉ. मुकेश जोशी, अल्मोड़ा ||131

30) छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति
डॉ. बन्सो नुरुटी, रायपुर ; छ.ग. ||135

31) प्रो. अमर्त्य सेन का व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवनवृत्त तथा उनके आर्थिक विचारों...
डॉ. मीनू पाण्डे, कानपुर (उ.प्र.) ||138

32) सोशल मीडिया का विद्यार्थियों के मानव मूल्यों पर प्रभाव
डॉ. मंजू चौधरी, सरोज कंवर राठौड़, जयपुर ||143

33) भारतीय संघीय व्यवस्था में बदलाव : लोकतांत्रिक आधार पर पंचायती राज....
डॉ. श्याम नारायण, हमीरपुर ||147

34) मिथक : समकालीनता में पापुलर लिटरेचर
दिवाकर विक्रम सिंह, झांसी ||149

35) कारीगर एवं शिल्प कौशल
Smt. Needhi Singh, Arun Kumar Singh, Chhattisgarh ||154

36) भारत पाकिस्तान संघर्षों में वाह्य शक्ति की भूमिका
वासुदेवन मणि त्रिपाठी, रत्नेश कुमार, प्रयागराज ||156

37) जीवन मूल्यों का अर्थ
सतीष यादव, ग्वालियर, (म.प्र.) ||160

38) छत्तीसगढ़ के शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण
डॉ. प्रकृति जेम्स, सत्यप्रकाश यादव, छत्तीसगढ़ बिलासपुर ||168

39) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का कार्यान्वयन एवं उपलब्धि
डा. पूनम कुमारी, सहरसा (बिहार). ||171

40) स्नातकोत्तर स्तर अनुसूचित, पिछड़े एवं सामान्य जाति विद्यार्थियों के व्यक्तिगत मूल्य
पूनम राठौर, प्रो. भावेशचन्द्र दूबे, मेरठ। ||175



छत्तीसगढ़ के शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं का अकादमिक उपलब्धियों की उत्तमता के संबंध में 'संपूर्ण गुणवत्ता मूल्यांकन'

डॉ. प्रकृति जेम्स

शोध निर्देशिका

सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त)

वि.वि. छत्तीसगढ़ बिलासपुर

सत्यप्रकाश यादव

शोधार्थी (शिक्षा)

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त)

वि.वि. छत्तीसगढ़ बिलासपुर

प्रस्तावना (Introduction)

शिक्षा की दृष्टि से "प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण", "गुणवत्तापूर्ण सभी के लिए शिक्षा", आदि राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख लक्ष्य रहे हैं। इसी क्रम में 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देना, आज उनका मौलिक अधिकार बन गया है, साथ ही यह लक्ष्य देश का संवैधानिक उत्तरदायित्व भी हो गया है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में हम यह कह सकते हैं शिक्षण जैसे उत्तम में कार्यशिक्षक की भूमिका केन्द्रीय हो गई है। वर्तमान समय में शिक्षक से हमारी अपेक्षाएँ बढ़ गयी है, आज उसे जहाँ स्वयंविद्यार्थी, समाज, शाला, व्यवसाय इत्यादि के प्रति समर्पित होना है, वहीं विशय-विशेषज्ञ, चिंतक के रूप में भी अपने को साबित करना है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1996 के अनुसार शिक्षा के चार स्तम्भ- ज्ञान के लिए सीखना, स्व-अस्तित्व के

लिए सीखना, कार्य के लिए सीखना एवं सहअस्तित्व के लिए सीखना है, इन चार स्तम्भों का आधार शिक्षक है। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, इन अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु एक कुशल शिक्षक तैयार करना होगा और यह तभी संभव है जब देश में शिक्षक को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए मानक के अनुसार सुविधा सम्पन्न उच्च कोटि शासकीय- अशासकीय की शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाएँ हो। देश के सभी राज्यों में ऐसी संस्थाओं के गठन हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये जा रहे हैं।

इसी तारतम्य में स्थानीय एवं जिला स्तर पर प्रारंभिक शालाओं के शिक्षकों को सेवापूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण देने तथा सभी प्रकार के उत्तरदायित्व और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाएँ संचालित की गयी है और इनकी संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। इन संस्थाओं के प्रमुख लक्ष्य निम्नानुसार वर्णित है -

❖ प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण करना।

❖ प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफल बनाने की दृष्टि से अकादमिक तथा अन्य संसाधनों की पूर्ति करना।

❖ प्रशिक्षण संस्थाएँ स्वयं को इतना उन्नत बनायेगी कि उनसे प्रारंभिक शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहायता मिल सके।

❖ जिले की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिये योजनाओं का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन करना।

❖ अध्यापकों को उच्चस्तरीय सेवापूर्व-सेवाकालीन प्रशिक्षण देना।

❖ अध्यापक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में आस-पास के साधनों का अधिकतम प्रयोग कर सकें।

❖ प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययन-अध्यापन की सहायक सामग्री का निर्माण करना तथा मूल्यांकन उपकरण निर्मित करना।

❖ क्रियात्मक अनुसंधान पर बल देना।

❖ दिव्यांगों एवं वंचित वर्ग के बच्चों की

समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करना।

अपेक्षा लक्ष्यों को पूरा करने हेतु प्रारम्भिक

शालाओं के शिक्षकों को उच्च स्तर पर प्रशिक्षण देने एवं सभी प्रकार के संसाधन हेतु डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाएँ स्थापित की गयीं। डी.एल.एड. अध्यापक शिक्षा का व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य कक्षा आठवीं तक के अध्यापकों को तैयार करना है। डी.एल.एड. पाठ्यक्रम का उद्देश्य समाज की सहभागिता से सामाजिक विषमताओं को दूर करते हुए समावेशी स्कूल पर्यावरण में सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की बुनियादी आवश्यकता को पूरा करना है। शासकीय एवं अशासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को कार्य करते लम्बा समय बीत चुका है अब उनके कार्य प्रणाली, अध्यापकीय व्यवहार, एवं दक्षता का मूल्यांकन का उपयुक्त समय आ चुका है। देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में शासकीय एवं अशासकीय शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं यह शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन संस्थानों को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) तथा सर्वशिक्षा अभियान जैसे महत्वकांक्षी राष्ट्रीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का आधार मानते हुये, इन्हें सभी प्रकार की अधुनातन सुविधायें एवं तकनीक उपलब्ध कराने हैं जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नयी दिल्ली (NCTE) ने मानक व दिशा निर्देश निर्धारित किये हैं।

संबंधित शोध साहित्य का अध्ययन

बनर्जी (१९६७) ने भारत में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण पर अध्ययन किया। इनके अध्ययन के निम्न परिणाम थे कि शिक्षक प्रशिक्षण में बहुत सी कमियाँ थीं। परिवर्तनों और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिक्षक प्रशिक्षण में आमूल परिवर्तन और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिक्षक प्रशिक्षण में आमूल परिवर्तन आवश्यक था। मूल्यांकन व शिक्षण पद्धतियाँ पुरानी थीं।

मूलैया (१९६८) ने मध्यप्रदेश में शिक्षक प्रशिक्षण की स्थिति का अध्ययन किया। इस अध्ययन का निष्कर्ष यह प्राप्त हुआ कि मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय का अभावग्रस्त थे। विद्यालयों में संसाधनों की कमी थी। मूल्यांकन और शिक्षण

विधि परंपरागत थी। पुरुषों की संख्या महिलाओं की अपेक्षा अधिक थी।

गुप्ता (१९८०) द्वारा माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता पर अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के यह परिणाम निकले कि शिक्षक प्रशिक्षकों की शैक्षिक योग्यता एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण में सह संबंध होता है। शिक्षण अनुभवों का प्रशिक्षण कार्य पर प्रभाव पड़ता है। समाजोपयोगी कार्य व्यावसायीकरण सामुदायिक कार्य व शिक्षण पद्धति आदि का ज्ञान देना आवश्यक है।

गुप्ता (१९८२) द्वारा भारत में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया है। इस अध्ययन के ये परिणाम प्राप्त हुए कि ६१ से ७० के बीच संस्थानों की वृद्धि हुई है। ८३ प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षक पुरुष थे। प्रशिक्षक संस्थानों की कार्य प्रणाली प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन प्रणाली परंपरागत थी। ज्यादा गांवों से संबंधित थे। केवल १८ प्रतिशत छत्र एम.एड. उपाधि प्राप्त थे। शैरीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को महत्व नहीं दिया जाता था। स्थानीय संस्थानों की व्यवस्था से ठीक थी। वाद-विवाद विधि ज्यादा प्रचलित थी।

राय (१९८२) ने उत्तर प्रदेश तथा गुजरात के शिक्षा महाविद्यालयों और अभ्यास शिक्षण शालाओं (Practice Teaching Schools) से संबंधित समस्याओं पर अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला है कि :-

- शिक्षा महाविद्यालयों एवं अभ्यास शालाओं के परिप्रेक्ष्य में अनेकों कमियाँ उजागर हुई हैं। शिक्षा महाविद्यालयों एवं अभ्यास शालाओं के बीच परस्पर सहयोग का अभाव के साथ-साथ यह भी पता चलता है कि शिक्षा महाविद्यालय के प्रशिक्षार्थियों द्वारा अभ्यास शालाओं में जाने से उनके कार्यक्रम, एवं अन्य नियमित गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होती है।

- इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि अभ्यास शालाओं एवं शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रभावशाली सहयोग होना चाहिए।

सिन्हा (१९८२) ने बिहार में शिक्षक-शिक्षा विषय पर अध्ययन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि -

• प्राथमिक स्तर पर लगभग ६० प्रतिषत शिक्षक-प्रशिक्षक बी.एड. प्रशिक्षित हैं परन्तु उनका कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया।

• ७० प्रतिशत महाविद्यालय में स्वयं का भवन नहीं पाया गया और ६५ प्रतिषत महाविद्यालयों में दयनीय स्थिति वाले भवन पाये गये।

• अधिकांश शिक्षा महाविद्यालयों में स्टॉफ, पुस्तकालय, उपकरण तथा प्रयोगशाला अपर्याप्त पाये गये।

• आधुनिक नवाचारी कार्यक्रमों का समावेश अभी तक शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों में नहीं हो पाया है।

• सेवाकालीन प्रशिक्षण न तो प्रभावशाली ढंग से दिये जाते हैं और न ही अध्यापन अभ्यास कार्य करने में पर्यवेक्षक शिक्षक पर्याप्त ध्यान देते।

अध्ययन का औचित्य

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विष्वविद्यालय (NUEPA) तथा डाईट जैसी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं के द्वारा योजना के क्रियान्वयन, लक्ष्य प्राप्ति तथा उससे अपेक्षाओं पर किये गए राष्ट्र स्तरीय मूल्यांकन निष्कर्ष बहुत अधिक सकारात्मक एवं उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं।

इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ में संचालित डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में मानको के अनुरूप कार्यों का मूल्यांकन करना विषेश शैक्षिक महत्व का होगा क्योंकि इस शोध अध्ययन के निष्कर्ष के प्रकाश में डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं की वास्तविक स्थितियों का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा और समय रहते ही योजनाबद्ध ढंग से उनकी त्रुटियों को सुधारने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इस संदर्भ में यह पता लगाना कि छत्तीसगढ़ राज्य कि विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में सेवारत आचार्य अपने-अपने संस्थाओं कि अपेक्षाओ सुविधाओ, प्रयासो, क्रियाकलापों, गुणवत्ता आदि से कितना परिचित है उनकी सजगता इस ओर कितनी है, विषेश महत्व का है क्योंकि आचार्यों की ऐसी ही परिकल्पनाओं, अवबोध तथा सजगता पर राज्य में डी.एल.एड. प्रशिक्षण

कि योजना की सफलता निर्भर करती है। इसलिए एक ऐसा शोध अध्ययन जिससे निम्नलिखित शोध-प्रश्नों के हल ढूँढ जाये, छत्तीसगढ़ राज्य में सुदृढ़ प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था के लिए अत्यंत औचित्यपूर्ण होगा क्योंकि इस नवोदित राज्य में इस प्रकार का अध्ययन अभी तक चरितार्थ नहीं हुआ है। इस सर्वेक्षणात्मक अध्ययन के निष्कर्ष राज्य के लिए दिशा निर्देशक होगा।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं -

❖ शासकीय तथा अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण की संस्थाओं की अकादमिक उपलब्धियों की उत्तमता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना-

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों की जांच हेतु शोध-प्रश्नों के रूप में निम्नांकित परिकल्पनायें बनायी गयी हैं -

❖ शासकीय तथा अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण की संस्थाओं की अकादमिक उपलब्धियों की उत्तमता में अंतर होता है।

प्रस्तावित शोध विधि (Research Method)

प्रस्तुत अध्ययन एक वर्णात्मक अध्ययन है जिसमे सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया जायेगा।

न्यादर्ष (Sample)-

न्यादर्श के रूप में शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत प्राचार्य, प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षार्थी रहेंगे। प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के २ जिलों में संचालित २ शासकीय डाईट्स (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों) एवं २ अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थायें अध्ययन का समग्र है।

अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं को यादृच्छिक विधि से चुन इन प्रशिक्षण संस्थाओं की १ यूनिट (५० सीट) के प्राचार्य, प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षार्थी न्यादर्श में शामिल हैं।

अध्ययन के चर-

प्रस्तुत अध्ययन में चर एवं उनके स्तर

अनुसार है -

स्वतंत्र चर (Independent Variable) -

डॉ. डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली द्वारा निष्पन्न कार्यक्रम एवं मानक प्रस्तुत अध्ययन में स्वतंत्र चर है।

संबंधित स्वतंत्र चर—(Associated Variable)

संस्थाओं के प्रकार :-

- शासकीय
- अशासकीय

आश्रित चर (Dependent Variable)

शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में सम्पूर्ण गुणवत्ता का मूल्यांकन गुणात्मक सूचक (Indicator) इस अध्ययन के आश्रित चर है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा वर्णित है, के माध्यम से किया गया है।

❖ अकादमिक उपलब्धियों यथा - पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण में उत्तमता। उपकरण (Tool)

प्रस्तुत शोध अध्ययन में तीन उपकरणों का उपयोग किया जायेगा। तीनों उपकरण अध्ययनकर्ता द्वारा निर्मित होंगे। तीन उपकरण निम्नानुसार है -

- > प्रशिक्षार्थियों के लिए प्रश्नावली
- > शिक्षक-प्रशिक्षकों हेतु प्रश्नावली
- > संस्था के प्राचार्य हेतु साक्षात्कार पत्रक प्रदत्तों का विप्लेशन

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हुए प्राचार्य एवं अध्यापन कर रहे आचार्यों से एवं प्रशिक्षार्थियों से प्रश्नावली के माध्यम से प्रदत्त संकलन किये गए।

अकादमिक सुविधाओं व कार्य संबंधी निष्कर्ष

(अ) प्रशिक्षण -

> प्रदर्शन कक्षाओं एवं ब्लॉक-टीचिंग कक्षाओं की संख्या पर्याप्त नहीं पायी गयी। इनकी संख्या अध्यापन-कौशल विकसित करने हेतु बढ़ायी जानी चाहिए तथा लगभग ९५ प्रतिशत शिक्षक-प्रशिक्षकों के अनुसार स्कूल स्तर के सभी विषयों में छात्राध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

> लगभग ८७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अध्यापन में प्रोजेक्ट सहायक सामग्री का उपयोग होना चाहिए। कक्षागत अन्तर्क्रियाओं में मूल्की-मीडिया के उपयोग से बेहतर समझ विकसित होती है, ऐसी मान्यता लगभग ९० प्रतिशत उत्तरदाताओं का है।

> मॉडल स्कूलों में छात्राध्यापकों से अध्यापन-अभ्यास कराकर उनके अध्यापन कौशल में सुधार किया जा सकता है।

> लगभग ७० प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अभ्यास किया है कि पाठ्य योजनाओं का अनुमोदन मात्र एक बकवास है।

> छात्राध्यापक कक्षाध्यापन में सही ढंग से अध्यापन सहायक सामग्री का उपयोग नहीं कर पाते। अध्यापक अभ्यास कक्षाओं में कठिन प्रकरणों का अध्यापन करने से कतराते हैं।

(ब) पाठ्यक्रम -

> डाईट्स के वर्तमान पाठ्यक्रम पुनरुद्धान की आवश्यकता है (८९%) तथा वर्तमान प्राइमरी स्कूल टीचर एजुकेशन के पाठ्यक्रम को पूर्णरूपेण नये सिरे से संशोधित करने की आवश्यकता (७०%) है।

सन्दर्भ ग्रंथ (Reference)

चन्द्रशेखर, के. (२०००)- एन इवैल्यूएटिव स्टडी आफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम इन आन्ध्रप्रदेश, पी-एच.डी. थिसिस, एजुकेशन श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति।

चन्द्रशेखर, के. (२००७)- " टीचर एजुकेशनस पर्सपेक्स आफ डाईट्स फेसीलिटीज एण्ड दीयर रिलेसन्स टू सर्टेन पर्सनल एण्ड डिमोग्राफिक वैरियेबल्स" पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन हरिनगर रिसर्च बडौदा, वाल्यूम २३ (२), अप्रैल २०१७ पृष्ठ १२-१०४

डेलर्स, जे. एट. आल (१९९६) : 'क्वालिटी टीचर्स, लर्निंग: दी टेजर विदिन' रिपोर्ट टु यूनेस्को ऑफ दी इण्टरनेशनल कमीशन आन एजुकेशन फार दी ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी, पृष्ठ-१४६ पेरिस, यूनेस्को, कोटेड इन दी इण्डियन्स जर्नल फार टीचर एजुकेशन, एन.सी.टी.ई., नई दिल्ली, वाल्यूम :१) , अगस्त १९९८

एन.आर.सी.एण्ड जंगीरा, एन.के. (२००४) 'ए
नई दिल्ली, एन.सी.ई.आर.टी. पृष्ठ :
१-७८९

दीपा कृष्णा एण्ड सरोज आनन्द (2006),
प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण—जिला शिक्षा
संस्थाओं की भूमिका अन्वेषिका ३ ; २)
जून २००६, पृष्ठ ७५ से ८०

गवर्नमेंट आफ इंडिया (१९८९)— गाइडेन्स
नई दिल्ली, मिनीस्टरी आफ ह्यूमन रिसोर्स
डेवेलपमेंट, डिपार्टमेंट आफ एजुकेशन कोटेड इन
नई दिल्ली इन एजुकेशन, वाल्यूम २३ ; २), अप्रैल
२००७

गायत्री, ए. (१९९६)— एन इनवेस्टीगेशन
इंटू पर्सपेक्सिव आफ स्टूडेंट टीचर्स आन देयर टीचर
इंग, अनपब्लिस्ड एम.एड. डिजिटेशन, एस.व्ही.
केव्हाल, तिरुपति

गौड़, यशवन्ती (२०१३)— "जयपुर जिले
इं बी. एस. टी. सी. संस्थाओं में शैक्षिक गुणवत्ता हेतु
हो जा रहे प्रयास"— एक विश्लेषणात्मक अध्ययन,
पे-एच.डी. थिसिस एजू. वनस्थली, राजस्थान

सिंह, विनीता (२००९-१०)— " "
छत्तीसगढ़ राज्य की जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं
के सुविधाओं के विषय में प्रारंभिक शिक्षक—प्रशिक्षकों
का प्रत्यक्ष बोध: उनकी आयु, लिंग, शैक्षिक योग्यता
व्याख्यापन अनुभव के विशेष सन्दर्भ में एक
विश्लेषणात्मक अध्ययन रिसर्च थीसिस, बिलासपुर
(छ.ग.)

□□□